भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2504 सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

बुंदेलखंड में रोजगार

2504. श्री नारायणदास अहिरवार:

क्या अम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसका मुख्य कारण युवाओं में तेजी से बढ़ता पलायन है, क्योंकि वहाँ आजीविका का अभाव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थायी और स्थानीय रोजगार के अवसर मृजित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, लघु एवं कुटीर उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालयों को मजबूत करने और युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए कोई ठोस पहल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) एवं (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) दवारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, बुंदेलखंड क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः वर्ष 2017-18 में 6.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.1% और वर्ष 2017-18 में 4.3% से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.0% हो गई है।

सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र सिहत देश में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, वस्त्र, चमड़ा आदि जैसे कार्यकलापों में लगे कुटीर उद्योगों सिहत नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रही है।

बुंदेलखंड क्षेत्र सिहत सभी के लिए रोजगार मृजन और नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार मृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मिनर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस योजना का एक उद्देश्य रोजगार कार्यालयों को आदर्श किरयर केंद्रों (एमसीसी) में बदलना है। ये केन्द्र प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ-साथ किरयर परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवाओं तथा रोजगार चाहने वाले अन्य व्यक्तियों को रोजगार अवसरों से जोड़ते हैं। इस प्रकार, ये आदर्श किरयर केन्द्र (एमसीसी) राज्यों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए आउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से रोजगार मेलों के आयोजन, नियोक्ताओं को संगठित करने, स्थानीय स्तर पर किरयर परामर्श प्रदान करने आदि के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। अब तक, बुंदेलखंड क्षेत्र सिहत उत्तर प्रदेश राज्य में 39 मॉडल किरयर केन्द्र तथा मध्य प्रदेश राज्य में 13 आदर्श किरयर केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं।
